के मेजीस्ट्रेट के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह राज्य सरकार की राय में बाल मनोविज्ञान और बाल-कल्याण का विशेष ज्ञान नहीं रखता है। यह भी मैं माननीया मन्त्री महोदया से प्रार्थना करूंगी कि कौन सा व्यक्ति मेजीस्ट्रेट नियुक्त किये जाने के योग्य है ? पर्याप्त योग्यता का मानदण्ड क्या है इसकी गाइडलाइन और भी सुस्पष्ट होनी चाहिये। महोदया, सेक्शन 6 (1) में जिला मेजीस्ट्रेट बोर्ड या किशोर न्यायालय के रूप में काम कर रहा है इस प्रकार का विवेचन है। लेकिन यह कैसे संम्भव है जबकि सेक्शन 6 (3) के अनुसार उसको बाल मनोविज्ञान और बाल कल्याण इत्यादि का खास ज्ञान होना आवश्यक है। जिला मेजीस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव हैड है और उसे दिये हुए अधिकार एक्स-आफिशियो हैं क्या उसको किशोर न्यायालय जैसे खास क्षेत्र में इस प्रकार का एक्स-आफिशियों अधिकार देना उचित है ? सब सेक्शन 7 (2) में भी इस प्रकार का ट्रांजिटरी प्रावधान है लेकिन मुझे तो लगता है कि ऐसी व्यवस्था करने के बजाय योग्य किशोर कोर्ट स्थापित करने पर ही जोर देना जरूरी है। हर क्षेत्र में इस प्रकार के कोर्ट्स स्थापित करने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए एक कालबद्ध योजना बनाने की जरूरत है।

मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगी कि क्या इस प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? आप इस मामले पर थोड़ा प्रकाश डालेंगी।

महोदया, चैप्टर 5 में बोर्ड या किशोर न्यायालय में केसेज चलाने के बारे में बड़े विस्तृत आदेश दिये गये हैं, खास करके इसकी प्रोसिडिंग्ज गुप्त रहे, किशोर का नाम वगैरह गुप्त रहे, इस पर जोर दिया गया है और जो ऐसी गुप्तता को भंग करेगा, यानी कि सब-सैक्शन 36(1) को भंग करेगा उसे एक हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है। यह स्वागत योग्य है।

चैप्टर 6 में जो किशोर के बारे में जो अपराध किये जा सकते हैं, उनका जिक्र किया है। इस चैप्टर की पांच सैक्शंस हैं और उसमें अलग-अलग अपराधों का विवेचन किया गया है और उनके लिए अलग-अलग सजाओं का प्रबंध किया गया है। तीन साल तक की सजा और जुर्माना इसके अन्तर्गत हो सकता है। इस प्रकार इस कानून को जरा कड़ा बनाया गया है। सजा बढ़ाने से यह कानून थोड़ा कड़ा हो गया है और किशोरों के बारे में जो भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं, उनके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है।

यह जो किशोरों को भीख मांगने के लिए बिठाते हैं, यह बहुत बड़ा अपराध है, यह इसमें माना गया है। इसके लिए तीन साल तक के लिए सजा हो सकती है। मुझे तो लगता है कि इस तरह के अपराधी को और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पैसे के लालच में आकर कुछ शैतान बच्चों के हाथ-पांव काट देते हैं, तोड़ देते हैं, आखें निकाल देते हैं और उनको भीख मांगने के लिए बिठाते हैं। अर्थात्, ऐसी हरकतों के लिए दूसरे एक्ट्स में बहुत भारी सजा दी गई है, लेकिन इस एक्ट के अन्तर्गत भी जरा कड़ी सजा होनी चाहिए।

वैसे देखा जाए, तो यह विधेयक बड़ा विस्तृत और सुगठित है और जुवेनाईल के जीवन को सुधारने में अच्छी सहायता देगा, लेकिन इन बदनसीब किशोरों का नसीब पलटने के लिए समाज, सामाजिक संस्थाओं और हरेक जिम्मेदार नागरिक को सरकार के साथ हाथ बंटाना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के जो सोशल लेजिस्लेशंस होते हैं, वह कामयाब हो सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

PAPERS LAID ON THE TABLE—
Contd.

Corrigenda to the Accounts (1984-85) of the Central Silk Board and the Statement giving reasons for the delay in laying thereof

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Krishna Kumar could not lay the papers on the Table of the House this morning. He is here. If the House agrees, we may permit him to lay the papers. Shri Krishna Kumar.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): Madam, I deeply regret that I was not here when my name was called. With your permission, I beg to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Corrigendum to the Annual Accounts of the Central Silk Board, for the year 1984-85.

(ii) Corrigendum to the statement giving reasons for the delay in laying the Annual Accounts of the Central Silk Board, for the year 1984-85.

[Placed in Library. *See* No. LT-3211/86 for (i) and (ii).]

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned for lunch. We will meet again at 2-30 P.M.

The House then adjourned for lunch at twenty-nine past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock. **The Vice-Chairman (Shri Pawan Kumar Bansal)** in the Chair.

THE JUVENILE JUSTICE BILL, 1986—Contd.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, this is an important Bill before us that we are considering. Sir, this is not a new legislation. There is an Act known as the Children's Act in the country already and I do not know what improvement is made in this new Bill over and above the existing law. The existing law, it is reported, is not properly functioning because of lack of funds. In that case, if you do not provide sufficient funds to the States, there is no use of getting any new law legislated. Sir, 35 per cent of the total population of the country constitutes the children. I mean to say, children covered by this new legislation are constituting to the extent of 35 per cent of the total population of this country and they are the future of the country. (*Interruptions*). Children are the precious wealth of the country. Future of the children is the future of the country. In that sense it is the most important Bill and we have to pay full attention to this Bill and we have to devote our entire energy to implement this new legislation effectively.

Sir, this Bill provides for care, protection, treatment development and rehabilitation of the children. If it is not properly implemented, there is a great danger in its misuse also, because some parents may be attracted by the provisions in the Bill and facilities for children in the Bill and they may prompt and inspire children to commit certain wrongs because they know that they will escape certain type of punishment. There is another disadvantage also. Criminals may also take advantage out if it. Our primary goal is not to send children to jails or in police custody. It is a welcome feature. But the criminals may take advantage out of it. They may prompt children to commit offences because there is no possibility of punishment for them. They cannot be sent to jails and they cannot be sent to police custody. Of course, it is a welcome feature that children are not sent to police custody. We know and we have been reading in the newspapers that police are known for torturing people in custody. They are known for being responsible for lock up deaths. They are also known for rapes and all that in jails. We have been reading in newspapers that criminals and prisoners are ill-treating children if they are put along with them. They have gone to the extent of fulfilling their devil desires with the children put in the jails. So, it is a welcome feature that children should not be sent either to jails or in police custody.

Sir, first of all, we must know what are the reasons for children becoming criminals. Children are not born criminals. They are made criminals. We